ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 208-209
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- I, Issues-23, YEAR- Jan.-March-2022

प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा की आवश्यकता

अर्चना श्रीवास्तव

शोध अध्येत्री – शिक्षा शास्त्र विभाग, बी. आर. ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुज्जफरपुर (बिहार), भारत

Received- 01.02. 2022, Revised- 05.02. 2022, Accepted - 08.02.2022 E-mail: archanasri2610@gmail.com

सारांशः – **प्राथमिक शिक्षा वह बुनियाद, जिस पर हमारी माध्यमिक और उच्च शिक्षा की ईमारतें खड़ी होती हैं। अतः हमारी प्राथमिक शिक्षा जितनी पक्की एवं सुदृढ़ होगी, शिक्षा रूपी ईमारतें भी उतनी ही ऊंचाई को सुदृढ़ता के साथ बनेगी। वैसे भी यह स्थापित व सिद्ध तथ्य है कि किसी भी समाज की प्रगति उसके नौजवानों के कन्धों की मजबूती पर निर्भर करता है और यह कन्धा प्रारम्भ। भारत के प्राथमिक शिक्षा की गति एवं दिशा के अध्ययन से मजबूत न किया मजबूत करने का प्रथम सरोकार राष्ट्र की सुदृढ़ता एवं उन्नति से सम्बद्ध है। प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन से यह बात उभरकर सामने आयी है कि यह अनेक विषमताओं की शिकार हैं, जिन्हें दो स्वरूपों में अभिव्यक्त किया जा सकता हैं– प्रथम, अंग्रेजी शिक्षा को आधार बनाकर शिक्षा प्रदान करने वाले पब्लिक स्कूल एवं द्वितीय, हिन्दी अथवा हिन्दी– अंग्रेजी सम्मिश्रणयुक्त सरकारी स्कूल। पब्लिक स्कूल आधुनिक सामयिक आवश्यकता अनुसार अंग्रेजी शिक्षा को महत्व दे रहें, किन्तु ये सामान्य जन की पहुँच से बाहर हैं , क्योंकि इनमें शुल्क एवं डोनेशन सभी जनता अदा नहीं कर सकती। दूसरी ओर प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से सबसे बदतर स्थिति परिषदीय विद्यालयों की है, जिसमें शिक्षा कम और अन्य गतिविधियों को अधिक अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ शिक्षा प्राप्त बच्चे अंग्रेजी में अत्यंत कमजोर होते हैं। प्रस्तुत शोधपत्र में इन्हीं बिन्दुओं पर चिन्तन को प्रस्तुत किया जा रहा है।**

कुंजीभूत शब्द– समिश्रण युक्त, प्राथमिक शिक्षा, आधुनिक सामयिक, लाभप्रद, उत्पादक, दीर्घकालिक, आदर्शवाद।

आज का समय 'ज्ञान' का है। इसीलिए सबसे लाभप्रद व उत्पादक संस्थाओं में शिक्षा को प्रथम स्थान प्रदान किया जा रहा है। वास्तव में 'शिक्षा' ही किसी राष्ट्र को बना सकती है, किसी व्यक्ति को उच्चतर प्रस्थिति प्रदान कर सकती है। शिक्षा का प्रभाव दीर्घकालीक होता है और पीढ़ियों तक इसका असर रहता है। आज यदि भारत का नाम पूरे विश्व में हुआ है, तो में उसका बहुत बड़ा कारण भारतीय इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, प्रोफेसर और साफ्टवेयर कम्प्यूटर इंजीनियर हैं। आज चीन हमसे तमाम क्षेत्रों में आगे है, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में हमसे पिछड़ा होने के कारण हमेशा सहमा रहता है, क्योंकि यह स्थिति भारत के लिए अपार सम्भावनाओं का द्वार खोल देती है। शिक्षा में भी अंग्रेजी भाषा की दृष्टि से चीनी विश्व में भारत से पिछड़ जाता है। इसीलिए दूसरे देश भी चीनियों के मुकाबले अंग्रेजी के कारण भारतीयों को प्राथमिकता देते हैं। भारत को यह प्रतिष्ठा तब मिली हुई है, जब अंग्रेजी भाषा को भारत के सरकारी स्कूलों में कक्षा– 6 से पढ़ाना आरम्भ किया जाता है। यह पाँच में साल का फासला उस छात्र को उसकी पूरी जिंदगी में पीछे ढकेल देता है। यद्यपि उत्तर भारत में नीजि स्कूलों में तो शुरू से अंग्रेजी पढ़ाई जाती हैं, किन्तु ऐसे स्कूलों तक समाज के सीमान्त लोगों की पहुँच नहीं है। दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात ऐसे राज्य हैं, जहाँ के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पाँचवी तक अंग्रेजी की शिक्षा नहीं प्रदान की जाती है।

'ज्ञान आयोग' ने इसे अपनी रिपोर्ट में रेखांकित किया है और अपने सिफारिश में कहा है कि 'भारत को 21वीं सदी की महाशक्ति के रूप में देखना है, तो अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिक स्तर से प्रदान किया जाना आवश्यक है। 'इसी के दृष्टिगत और अंग्रेजी के विश्व– भाषा के सम्पर्कसूत्र का दर्जा मिलने की वजह से प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा की अनिवार्यता सम्बन्धी बहस छिड़ गयी है। इस बारे में कोई कुछ भी कहे, कितना भी विरोध करे, असलियत यह है कि इस देश में क्या दुनिया में कहीं भी यदि तरक्की करनी है, तो अंग्रेजी शिक्षा की जरूरत को नकारा नहीं जा सकता है। अंग्रेजी जानने वाले हिंदी भी जानते हैं और उसका फायदा वे ले लेते हैं, लेकिन यदि हिंन्दी जानने वालों को अंग्रेजी नहीं आती है, तो वे राष्ट्रीय या अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर कोई फायदा नहीं उठा पाते हैं। बॉलीवुड के जितने बड़े स्टार हैं, सब अंग्रेजी में बोलते, सोचते हैं, केवल हिन्दी का डॉयलाग रट लेते हैं, भाषा की इसी पकड़ की वजह से वे सब करोड़पति बने हैं। हमारे कतिपय राजनेता अंग्रेजी को आदर्शवाद का मुल्लमा चढ़ाकर पेश करते हैं कि अंग्रेजी, अंग्रेजों की भाषा है और हमें इसका बहिष्कार करना है। इस सिलसिले में वे राम मनोहर लोहिया का उदाहरण देते चाहिए। वे यह नहीं जानते हैं कि डॉ० लोहिया की अंग्रेजी बहुत अच्छी थी और वे भी विदेश में पढ़े थे। इससे बड़े ताज्जुब की बात क्या हो सकती है कि भारत के जितने बड़े नेता हुए वे ज्यादातर विदेश में शिक्षा प्राप्त किये हुए थे। महात्मा गाँधी, जवाहर लाल नेहरू, जय प्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया, ज्योति बसु, इंदिरा गाँधी आदि सभी विदेशों में शिक्षा ग्रहण की थी। इसी प्रकार सरदार पटेल, चौधरी चरण सिंह, चन्द्रशेखर जी आदि की अंग्रेजी बहुत थी और उनकी रचनाएँ सामन्यतया अंग्रेजी में है।

इसी प्रकार, अधिकांश राजनेताओं के सन्तानों की शिक्षा– दीक्षा विदेशों में अंग्रजी भाषा में होता रहा है। अतः अंग्रेजी

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- I, Issues-23, YEAR- Jan.-March-2022

भाषा को लेकर एक झूठी सियासत होती रही है, जिसमें आप अपनी कमजोरी का गुस्सा आगे आने वाली पीढ़ियों के बच्चों पर उतारते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें खुद अंग्रेजी नहीं आती है, अंग्रेजी का विरोध करते हैं। यह उनकी कुण्ठा और हीनभावना की ही अभिव्यक्ति है। यदि वे इतने बड़े अंग्रेजी के विरोधी हैं तो यह विरोध अपने घर से क्यों नही शुरू करते हैं? ये लोग विरोध का एक तर्क और देते हैं कि अंग्रेजी के शिक्षक उपलब्ध नही हैं, इसलिए प्राइमरी स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाना मुश्किल है। कपिल सिब्बल ने संसद में बताया कि 5 लाख से ज्यादा शिक्षकों की जगह खाली है और सबसे ज्यादा रिक्त पद बिहार व उत्तर प्रदेश में है। यदि हम इन पदों पर प्राइमरी स्कूलों में एक. एक अंग्रेजी का शिक्षक रख नियुक्त कर लें, तो अंग्रेजी शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सकता है। यदि अंग्रेजी के शिक्षक कम मिलते हैं तो हम दक्षिण भारत से इसकी पूर्ति कर सकते हैं। यदि उत्तर भारत के एक गांव में एक घर दक्षिण भारतीय का होगा तो उत्तर– दक्षिण के संस्कृतियों का समन्वय होगा और लोग दक्षिण भारत की संस्कृति, खानपान, भाषा सब कुछ समझेंगे। यही प्रकार का अनुकरण दक्षिण भारतीय भी करने लगेंगे। अंग्रेजी की आवश्यकता के मद्देनजर केन्द्र सरकार को उत्तर भारत के सभी राज्य सरकारों पर दबाव डालना चाहिए कि वे प्राइमरी स्कूलों में कक्षा एक से ही अंग्रेजी को वैकल्पिक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में स्थान दें। इस बात से मानव संसाधन मंत्री श्री कपिल सिब्बल भी सहमत हैं।

झुग्गी– झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे भी अंग्रेजी पढ़ने के लिए बेताब हैं। उनके मां– बाप भी उन्हें अंग्रेजी पढ़ाने की लालसा संजोये हुए है, तॉकि झुग्गी– झोपड़ी की जिंदगी से बाहर निकल सकें। यदि इस प्रकार की पहल प्राथमिक स्कूलों में राजकीय स्तर पर हो तो एक बहुत बड़े परिवर्तन को हमारे समक्ष ला खड़ा करेगा। गाँवों में 80 प्रतिशत अभिभावक को इसलिए सरकारी प्राइमरी स्कूलों में नहीं पढ़ा रहे हैं कि यहाँ अंग्रेजी माध्यम से अथवा अंग्रेजी की शिक्षा प्रदान नहीं किया जाता है। अतः हमें अंतरराष्ट्रीय सम्पर्क भाषा अंग्रेजीय का प्रसार– प्रचार किया जाना चाहिए।

किन्तु, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भारतीय भाषाओं को गौढ बना दिया जाये। इसका आशय मात्र इतना ही है कि हमें अंग्रेजी को अन्तरराष्ट्रीय वैश्विक सम्पर्क के साधन के रूप में ज्ञानार्जन करना चाहिए, वास्तविक आत्मा तो हमारी देशी भाषाओं में ही अवस्थित है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Agrawal, J C, Landmark in the history of Modern Indian Education, Vikas Publishing House, New Delhi& 1954.
2. Naik, J-P-, The Education Commission and after- Allied Publishars] New Delhi& 1982.
3. Mukerjee, S- N-, Education in India to day and tommorow- UNESCO& Italy Publishers Pvt- Ltd- Delhi & 1973.

*****